aiiea

सेन्ट्रल जोन इंश्योरेंस एम्पलाईज एसोसियेशन

(ए.आई.आई.ई.ए. से संबद्ध)

33, प्रभांजलि, आर.डी.ए. कालोनी, टिकरापारा, रायपुर (छ.ग.)

cziea

अध्यक्ष : काम. अजित केतकर

महासचिव : काम. डी. आर. महापात्र

परिपत्र क्र. : 1/2023

दिनांक : 1/1/2023

मध्य क्षेत्र के समस्त साथियों के नाम

प्रिय साथियों ,

नव वर्ष - नव अभिनंदन

हम नव वर्ष 2023 के आगमन के अवसर पर देश-दुनिया के मेहनतकश आवाम, देश भर के बीमा कर्मचारी एवं मध्यक्षेत्र के समस्त साथियों को असंख्य शुभकामनाएं एवं क्रांतिकारी अभिनंदन प्रेषित करते हैं। नववर्ष की नयी सुबह सभी के लिए नवउत्साह और नव संदेश लेकर आये, जिससे आज से एक बेहतर कल का निर्माण किया जा सके, यही हमारी कामना है।

हालांकि, बीते हुए वर्ष के बाद नववर्ष की शुरुआत पुन: एक बार वैश्विक स्तर पर करोना के नये वेरिएंट की दस्तक से हो रही है, जिसने फिर एक बार कोविड महामारी के त्रासदी भरे दौर की भयावह यादों को सामने ला दिया है। निश्चय ही यह दुनिया के लिए और हम सभी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। हम यह अपेक्षा करते हैं कि 2020-2021 की त्रासदी से सबक लेकर इस बार मानवता को सुरक्षित रखने तमाम मुल्क की सरकारें इस पर गंभीर कदम उठाएंगी।

बीता वर्ष जाते-जाते विश्व मेहनतकश जनता के लिए पुन: आर्थिक महामंदी की आहट के शोर से सरोबार रहा है। रूस-यूक्रेन युद्ध ने भी इसमें योग दिया है। इससे पूंजीवादी-साम्राज्यवादी लूट की शिकार विश्व की आम जनता के समक्ष खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति के संकट और भीषण मंहगाई ने जनता का जीना मुहाल कर दिया है। एक ओर नवउदारवादी वैश्वीकरण की नीतियों से बढ़ती असमानता तो दूसरी ओर पूंजी के केन्द्रीयकरण से बढ़ती खरबपतियों की विपुल संपदा ने एक दुनिया को दो दुनिया में बदल दिया है। इससे उपजे असंतोष का लाभ दक्षिणपंथी राजनीतिक शक्तियां उठा रही हैं, जो मानव समाज को प्रगतिशील, वैज्ञानिक, अग्रगामी दिशा की बजाए प्रतिक्रियावादी, पुरातन, रूढ़िवादी घृणा व हिंसा की पिछड़ी सोच की ओर धकेल रही है। किंतु इस हालत में भी नवउदारवादी नीतियों और दक्षिणपंथी रुझानों के विपरीत विश्व मेहनतकशों के उनके ऊपर हो रहे आक्रमणों के खिलाफ मुखर हुए प्रतिरोध की ऊष्मा व आभा तथा लातिन अमरीकी देशों में जनपक्षधर वामजनवादी विकल्प की मौजूदगी और हाल ही में ब्राजील के चुनाव में धुर दक्षिणपंथी बोल्सेनारो की पराजय व लूला डी सिल्वा की विजय तथा विकसित देशों में भी मजदूर वर्ग के तीखे होते संघर्षों ने एक बेहतर दुनिया के निर्माण के संघर्ष तथा अमानवीय वैश्वीकरण-उदारीकरण-निजीकरण की नीतियों को ही शाश्वत बनाए जाने के प्रचारों के विपरीत आशा की नई किरणों का संदेश भी दिया है। नव वर्ष में संघर्षों की इस मशाल की लौ पूरी शक्ति से प्रज्जवलित होगी और रूस-यूक्रेन युद्ध की समाप्ति तथा विश्व में शांति कायम होगी, यही हमारी अपेक्षा है।

उपरोक्त प्रभावों से हमारा देश भी अछूता नहीं है। बीते वर्ष की समाप्ति और नव वर्ष के शुरुआत के इस समय में देश की अर्थव्यवस्था में भी मंदी की काली छाया की प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और रिजर्व बैंक ने भी आर्थिक वृद्धि के पूर्व के दावों को घटा दिया है। इसके चलते बेरोजगारी चरम पर है, मंहगाई विगत दो दशकों के सबसे उच्च स्तर पर है, आम लोगों की क्रय शक्ति घट रही है और बहुसंख्यक लोगों का जीवन नीचे की ओर जा रहा है। भूख सूचकांक हो या मानव विकास सूचकांक, लगभग सभी सूचकांकों में भारत का स्थान पूर्व से नीचे की ओर खिसक रहा है। यूं तो नोटबंदी, जीएसटी ने पहले ही अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी, करोना ने उसमें आहूति का काम किया था, अब मंदी की पुन: आहट और वर्तमान केंद्र सरकार की अंधाधुंध उदारीकरण की नीतियों ने परिस्थितियों को और भयावह बना दिया है। इस स्थिति में 'आपदा को अवसर में बदलने', 'आत्मनिर्भर भारत' के नाम पर केंद्र सरकार की नेशनल मोनिटाईजेशन, नेशनल लैंड मोनिटाईजेशन और सार्वजनिक क्षेत्र, उसमें भी रणनीतिक क्षेत्रों की औने-पौने दामों में बिक्री ने हालात को और अवहनीय बना दिया है। इसी दौर में देश में खरबपतियों की बढ़ती संख्या और बढ़ते पूंजी के केंद्रीकरण ने समाज में असमानता की चौड़ी खाई को अपनी सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। इससे किसान-मजदूर-छात्र-युवा-महिला समाज के हर हिस्से की बहुसंख्यक अवाम की वंचना बढ़ी है। केवल यही नहीं देश में सांप्रदायिक विभाजन , घृणा और हिंसा की राजनीति चरम पर है। देश की तमाम स्वायत्त संस्थाएं चाहे न्यायपालिका, सीबीआई, ईडी, इन्कमटेक्स, चुनाव आयोग, मीडिया हो या अन्य कोई और उनकी स्वायत्ता पर पर ही

प्रश्नचिन्ह है। लगभग सभी संस्थाएं निशाने पर हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो या फिर संवैधानिक व्यवस्थाएं, असल में संविधान के मूल आधार और प्रस्थापनाएं ही हमले की जद में हैं। यह देश के संघीय, लोकतांत्रिक व जनवादी आधार स्तंभ के लिए ही खतरे की घंटी का अहसास करा रही है। राज्य के संरक्षण में शासक वर्ग और मौजूदा शासक पार्टी के संरक्षण में एक देश, एक टैक्स से प्रारंभ होकर यह एक देश, एक सोच, एक रंग, एक खानपान, एक जीवन शैली, एक व्यवहार, एक आचरण, एक पार्टी और फिर एक व्यक्ति को ही अवतार के रूप में पेश करने की इन चेष्टाओं ने, विचारों के साथ-साथ हर किस्म की विविधता को समाहित कर, उसे एक सूत्र में पिरोकर, एक खूबसूरत भारत के निर्माण की परिकल्पना के समक्ष ही चुनौतियां उत्पन्न कर दी हैं। सरकार से प्रश्न करने वाले को ही राजद्रोह या देशद्रोह की संज्ञा देने की प्रवृत्ति में इसकी झलक साफ दिखाई दे रही है। निश्चय ही देश के मजदूर वर्ग के लिए यह एक गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि ये घटनाक्रम बुनियादी रूप से नवउदारवादी नीतियों के आक्रमणों और वर्गीय शोषण के खिलाफ उनकी वर्गीय एकता को ही खंडित करने की कोशिशों का हिस्सा है ताकि इसकी आड़ में वे देश के तमाम संसाधनों का चंद बड़े कार्पोरेट के हाथों में बिना किसी प्रतिरोध के हस्तांतरण सुनिश्चित कर सकें। देश के मेहनतकश जनता का इसके विरुद्ध निरंतर प्रतिरोध बीते वर्ष भी जारी रहा है और इस नये साल में यह और सुदृढ़ होगा ताकि हम अपने जीवन, आजीविका, एकता, भाईचारे और सबसे परे एक इंसान के रूप में अपनी पहचान कायम रखने में सक्षम होंगे, यही हमारी उम्मीद है।

बीता वर्ष सभी किस्म की बाधाओं के बाद भी हमारे प्रिय संस्थान एलआईसी की निरंतर प्रगति के बावजूद भी 17 मई 2022 को तमाम अतार्किक आधारों पर एलआईसी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कर वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा इसके 3.5 प्रतिशत शेयरों को बेचे जाने के काले अध्यायों का भी साक्षी रहा है। हालांकि एआईआईईए के सतत संघर्ष के चलते इसके विनिवेशीकरण को 28 वर्षों तक रोके रखने की उपलतब्धि भी एक ट्रेड यूनियन के लिए असाधारण उपलब्धि है। एलआईसी के विनिवेशीकरण का भारत सरकार का यह निर्णय और इस निर्णय के क्रियान्वयन के लिए अपनाए गए समय और प्रक्रिया कितने जनविरोधी, बीमाधारक विरोधी या फिर देश हित के विरुद्ध है, आईपीओ के बाद की वर्तमान स्थिति से यह और आईने की तरह साफ हो गए हैं। केंद्र सरकार के कदम यहीं तक रुके नहीं हैं बल्कि वे हर किस्म से एलआईसी को निजीकरण की तरफ धकेलने वर्गीय रूप से कितनी वचनबद्ध हैं, यह आईआरडीएआई की सिफारिशों, बीमा अधिनियम में प्रस्तावित किए जा रहे संशोधनों और निगम के कार्यों व नीतियों में परोक्ष-अपरोक्ष रूप से सरकार की बढ़ती दखलंदाजियों में भी साफ दिखाई पड़ रही है। इससे एलआईसी के व्यवसाय व कार्यप्रणाली तथा बीमाधारकों की बजाए शेयरधारकों को बेहतर प्रतिसाद के लिए नये बदलावों को थोपने से हमारे समक्ष नई चुनौतियां भी उभरी हैं। हमने अब तक देश के बीमाधारकों, आम जनता तथा एलआईसी के सभी श्रेणियों के श्रमिक वर्ग की एकता के बल पर इस महान संस्था की हिफाजत की है। हमें इस नववर्ष में भी उपरोक्त चुनौतियों का मुकाबला कर, हर कीमत पर अपने व देश के इस सर्वोत्तम वित्तीय संस्थान की रक्षा के लिए अपनी एकता व संघर्ष को सुनिश्चित करना होगा। इस नववर्ष के मौके पर पुनः हम यह पुनर्उद्घोषित करेंगे कि एलआईसी की सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में निरंतर प्रगति और हिफाजत के लिए न केवल हम संकल्पित हैं वरन् इसे नेस्तनाबूत करने की हर किस्म की राजनैतिक कोशिश को भी शिकस्त देने, हम एकजुट होंगे यही हमारा विश्वास है।

विगत वर्ष 1 अगस्त 2022 से हमारा नया मांगपत्र देय हो गया है, अपनी संस्था की प्रगति के अनुरूप हम जायज रूप से उसमें अपना हिस्सा प्राप्त करने के हकदार हैं। उद्योग में हमारे अनेक लंबित मुद्दों पर हमने समाधान प्राप्त किया है, अनेक मुद्दे जो आज भी लंबित हैं, उनका समाधान भी हमें प्राप्त करना है। वर्ष 2020 में नये साथियों की भर्ती के बाद सेवानिवृत्ति के बढ़ते दौर में उद्योग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में नई भर्ती के जरिये युवाओं को इस संस्था में भागीदारी का अवसर उपलब्ध कराने भी हमें 2023 में प्रयत्नशील होना होगा। निश्चय ही इसके लिए एक मजबूत संगठन आवश्यक है।

मेहनतकशों के लिहाज से मौजूदा सरकार व शासक वर्ग के द्वारा पेश की गई सबसे कठिनतम चुनौतियों के दौर में 2022 की विदाई और नववर्ष का आगमन यही संदेश दे रहा है कि अंधेरे के बाद ही रौशनी है। हम चुनौतियों को पीछे धकेलने, अंधेरे को नये सुबह की सूरज की रौशनी में तब्दील करने संपूर्ण शक्ति और एकता के साथ अपना संग्राम और मजबूत करेंगे, इसी विश्वास के साथ 'रात भर का है मेहमां अंधेरा, किसके रोके रुका है सबेरा' नये वर्ष 2023 की आप एवं आपके परिजनों को असंख्य क्रांतिकारी शुभकामनाएं।

रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं।
धरती के फैले आंगन में, पल दो पल है, रात का डेरा।
जुल्म का सीना चीर के देखों, झांक रहा है नया सबेरा।
रात के राही....

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ...

आपका साथी

(डी.आर. महापात्र)
महासचिव